

## झारखण्ड गजट

# असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 92 राँची, मंगलवार,

17 माघ, 1939 (श॰)

6 फरवरी, 2018 (ई॰)

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना 5 फरवरी, 2018

विषय:- सरकारी, भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अविध की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने के संबंध में।

संख्या-4/स.भू.(नीति)-17/2018-492/रा.,-- सरकारी, भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अविध की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है।

#### उक्त विषयों से संबंधित कार्यावली निम्नान्सार है :-

- 1. सरकारी भूमि की बंदोबस्ती/लीज बंदोबस्ती के संबंध में भूमि दर का सरलीकरण।
- 2. खासमहाल भूमि लीज नवीकरण की पद्धति व गणना के अनुरूप सरकारी भूमि के लीज का नवीकरण ।
- 3. रिक्त पड़े तथा Resume किये गये खासमहाल की भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दर का सरलीकरण ।
- 4. शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं के साथ सरकारी भूमि बंदोबस्ती पर रोक से संबंधित संकल्प संख्या-307/स॰को॰, दिनांक 23 जून, 2004 का निरस्तीकरण एवं सरलीकरण ।
- 5. अवैध दखल कब्जा की अविध से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-6144/रा॰, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-334/रा॰, दिनांक 14 मई, 2009 में समरूपता स्थापित करना ।
- 6. अन्यान्य ।

अतएव उक्त कार्यावली पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार को अनुशंसा करने हेतु निम्नवत् उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

1. म्ख्य सचिव, झारखण्ड

- अध्यक्ष।

2. विकास आयुक्त, झारखण्ड

- सदस्य।

3. अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड

- सदस्य।

4. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि स्धार विभाग, झारखण्ड

- सदस्य सचिव।

यह उच्च स्तरीय समिति 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी । प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**उदय प्रताप**, सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----